शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक-40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 29-06 अक्तूबर 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या प्रशासनिक प्रमुखों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपना सुक्खू सरकार का प्रयोग है या गलत राय

शिमला/शैल। 30 सितम्बर को छः माह का सेवा विस्तार भोगने के बाद प्रबोध सक्सेना 1990 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हो गये हैं। उनके स्थान पर 1988 बैच के आई.ए.एस. संजय गुप्ता को प्रदेश का अगला मुख्य सचिव बनाया गया है। लेकिन संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जबकि प्रबोध सक्सेना के साथ ऐसा नहीं था। मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने पर जो प्रतिक्रियाएं सरकार के फैसले पर जनता और पूर्व नौकरशाहों तथा विपक्ष की ओर से सामने आयी है उससे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर एक अलग सी बहस चल पड़ी है। क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसी को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सौंपी गयी हो। जबकि मुख्य सचिव के कार्यों के निष्पादन में अतिरिक्त कार्यभार के कारण कोई अड़चन नहीं आती है। ऐसे फैसले से फैसला लेने वाले के अपने ऊपर ही सवाल उठने लग जाते हैं। अब मुख्यमंत्री की प्रशासनिक समझ पर सवाल उठने लग पड़े हैं। क्योंकि इसी फैसले के साथ पुलिस और वन विभाग के प्रमुखों की नियुक्तियां भी चर्चा में आ गयी हैं। पुलिस प्रमुख और वन विभाग के प्रमुख को भी इन पदों की जिम्मेदारियां अतिरिक्त पदभार के रूप में ही सौंपी गयी हैं। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो मुख्यमंत्री को अपना पद त्यागने तक की राय दे दी है। यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि वह किसी भी अधिकारी को जब चाहे तब अपने पद से हटा सकता है। उसके लिये नियमित या अतिरिक्त कार्यभार से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। जो अधिकारी इन प्रमुख पदों पर तैनात हैं उन्हें भी अपने कार्य निष्पादन में अतिरिक्त कार्यभार के तमगे से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इस फैसले से अनचाहे ही प्रबोध सक्सेना का मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि सरकार ने उन्हें 30 सितम्बर को ही बिजली बोर्ड का तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सक्सेना 30 सितम्बर को अपना छः माह का सेवा विस्तार भोगने के बाद सेवानिवृत हो गये हैं और इस सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष नियुक्त हुये हैं। लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर जो अधिसूचना जारी की गयी है उसमें सेवानिवृत्ति का कोई जिक्र नहीं है। इससे यही लगता है कि उन्हें मुख्य सचिव के पद से हटाकर बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। स्मरणीय है कि सक्सेना को मिले छः माह के सेवा विस्तार को प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अतुल शर्मा ने चुनौती दे रखी है। इस चुनौती का आधार भारत सरकार के कार्मिक विभाग की अक्तूबर 2024 की अधिसूचना को बनाया गया है। क्योंकि सक्सेना पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई अदालत में चल रहे आपराधिक मामले में सहअभियुक्त हैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना सक्सेना की बतौर बिजली बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति में भी प्रासंगिक हो जाती है और इस नियुक्ति से अनचाहे ही सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो जाएंगे।

यह नियुक्ति की अधिसूचना

Government of Himachal Pradesh
MPP& Power Department

File No. MPP-B (2)-5/2025 Dated: Shimla-2, the 30.09.2025

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Prabodh Saxena IAS, (HP : 1990) as The Chairman, HP State Electricity Board Ltd. Shimla for a period of three years from the date of taking over as such, in the public interest.

Sh Prabodh Saxena IAS (HP:1990) shall work under the overall administrative control and supervision of the Hon'ble Chief Minister and shall be equivalent in rank, status, and responsibility to the post of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

The detailed Terms & Conditions of appointment shall be issued separately.

By order
Rakesh Kanwar, IAS
Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. As above Dated Shimla-2, the 30.09.2025

Copy for information and necessary action is forwarded to the following:-

1. The Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.
2. The Establishment Officer, Govt. of India, Ministry of Peronnel, PG & Pension, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi.
3. The officer concerned for information and further necessary action.
4. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, HP Secretariat, Shimla-2
5. The Pr. Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla-3
6. The Pr. Accountant General (A&E), HP Shimla-3
7. The Director (Energy), Directorate of Energy, 2nd Floor, Multistorey Parking, Shimla-5
8. The Managing Director, HPSEBL, Vidyut Bhawan, Shimla-4
9. The Managing Director, HPPCL, Himfed Building, BCS, Shimla-9
10. The Managing Director, HPPTCL, Tutikandi, Shimla-5
11. The Managing Director, HPSLDC, Tutu, Shimla.
12. The Chief Electrical Inspector, Electrical Inspectorate, Kasumpti, Shimla-9
13. The Secretary, HP Electricity Regulatory Commission, Kasumpti, Shimla-9
14. The Controller (Printing & Stationary), Govt. Press, Shimla.
15. Guard file.

Secretary (Power) to the
Government of Himachal Pradesh

एम्स बिलासपुर ने तीन वर्षों में की उल्लेखनीय प्रगति:नड्डा

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में एम्स बिलासपुर के तीसरे स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। उनके साथ लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर नड्डा ने कहा उन्नत एमआरआई, सीटी स्कैनर, पीईटी-सीटी, एंडोस्कोपी सुइट्स और ब्रोंकोस्कोपी सुइट्स जैसीअत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्स बिलासपुर ने अपनी स्थापना के केवल तीन वर्षों के भीतर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा आस-पास के राज्यों के लोग भी एम्स बिलासपुर में इलाज के लिए आ रहे हैं, यह तथ्य इस संस्थान में लोगों के बढ़ते विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

नड्डा ने गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर देखभाल और गुर्दा प्रत्यारोपण में उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि निजी व्यय में कमी रही है। जहां पहले लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वहीं आज एम्स बिलासपुर इस क्षेत्र की उच्च स्तरीय तृतीयक चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के संबंध में बताया कि हाल ही में एम्स बिलासपुर के लिए 127 पद स्वीकृत किए गये हैं, जिनमें 29 संकाय और 98 गैर-संकाय पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चयन समिति एक वर्ष तक सक्रिय रहेगी और इन पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कम से कम चार साक्षात्कार आयोजित करने के लिए अधिदेशित है।

नड्डा ने दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए एम्स बिलासपुर में 500 बिस्तरों वाले विश्राम सदन की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, टाइप III, IV और V क्वार्टरों के निर्माण के साथ-साथ स्नातक छात्रों के छात्रावासों के लिए 165 करोड़ रुपये और एक इनडोर स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

नड्डा ने पिछले 11 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा देश में इस समय 808 मेडिकल कॉलेज हैं। सालाना स्नातक मेडिकल सीटें लगभग 35,000 से बढ़कर 1.25 लाख हो गई हैं। पिछली कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,000 नई स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि अगले पाँच वर्षों में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें शुरू की जाएंगी।

दशहरा पर्व आस्था, एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीकःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला कुल्लू के रथ मैदान में सप्ताह भर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय

कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने भगवान रघुनाथ जी की पारम्परिक रथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं।

मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जहां दुनियाभर के लोग अलग-अलग ढंग से दशहरा मनाते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालु भगवान रघुनाथ जी के रथ को खींचकर समृद्ध परम्पराओं का निर्वहन कर सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल उत्सव हीं नहीं, बल्कि यहां के लोगों की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का भी प्रतीक है।

शुक्ल ने कहा कि हिमाचल और विदेश के युवाओं में केवल यही भिन्नता है कि यहां के युवा हिमाचल के युवा समृद्ध संस्कृति के संरक्षक हैं। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेकर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। यहां के युवा प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से जुड़कर इसका संरक्षण कर रहे हैं।

राज्यपाल ने सभी देवताओं से हिमाचल को नशामुक्त राज्य बनाने की प्रार्थना की। उन्होंने इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों से सामुहिक प्रयास करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान किया। उन्होंने नागरिकों से नदियों और नालों के समीप निर्माण कार्य न करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने सरकारी विभागों, बोर्डो, निगमों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

राज्यपाल ने कहा कि यह उत्सव सभी को एकसूत्र में पिरोता है तथा प्रदेश की समृद्धि का प्रतीक है। इससे हम राज्य के सौहार्दपूर्ण और उज्ज्वल भविष्य के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।

इस उत्सव में कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक देवी-देवता भाग ले रहे हैं।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंति पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने सतत संघर्ष और सत्याग्रह की शक्ति से देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित किया और उनके इस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए सभी से सामाजिक बुराइयों को मिटाने और नशा-मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे जनता की गरीबी और दुःख को भली-भांति महसूस करते थे और अंत तक निरंतर देशवासियों के हित के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि आज उनके आदर्शो और सिद्धांतों पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सीटीओ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की प्रगति में शास्त्री जी के योगदान को स्मरण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला पुलिस के लिए दो नए वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई।

राज्यपाल की धर्मपत्नी जानकी शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक हरीश जनारथा, उपमहापौर उमा कौशल, शिमला नगर निगम के पार्षदगण, उपायुक्त अनुपम कश्यप सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मनाली क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने कुल्लू और

मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से का भी जायजा लिया, जो बाढ़ के दौरान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने नदी के मार्ग बदलने से कई स्थानों पर हुए व्यापक नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की।

राज्यपाल ने सोलंग गांव का भी दौरा किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है तथा सड़कें और आसपास के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर सड़क दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई है और उचित मरम्मत एवं सुधार के लिए तत्काल इंतजाम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

राज्यपाल ने बिंदु ढांक, मनालसू नाला, आलू ग्राउंड और चौड़ीबिहल सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया।

सीमा सड़क संगठन और ग्रैफ के अधिकारियों ने राज्यपाल को पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत करवाया।

सोलंग गांव में भू-स्खलन पर राज्यपाल ने कहा कि गांव को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। यहां जिस तरह कृषि भूमि बह गई है, लोगों का पुनर्वास करना और भी कठिन हो गया है। उन्होंने इस संबंध में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, उपायुक्त तोरुल एस रवीश, पुलिस अधीक्षक डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन और बीआरओ एवं ग्रैफ के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दशहरा उत्सव पर प्रदेशवासियों को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व न केवल हमारे नैतिक मूल्यों और परम्पराओं को मजबूत करता है, अपितु यह संदेश भी देता है कि बुराई का अंत हमेशा निश्चित होता है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली लाएगा।

प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें: राजीव कुमार

शिमला/शैल। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार ने विभागीय अधिकारियों और

कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का और अधिक प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार करने की दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लाएं।

उन्होंने विभागीय निदेशालय और फील्ड स्तर के अधिकारियों से सफलता की कहानियों और विकासात्मक फीचर के जरिये सरकार की उपलब्धियों और लक्षित समूहों को प्राप्त हो रहे लाभों को प्रचारित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग पर यह बड़ा उत्तरदायित्व है कि इनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचे ताकि ज़रूरतमंद इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

राजीव कुमार ने कहा कि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ-साथ नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

बैठक के दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न शाखाओं से जुड़े मामलों का फीडबैक भी लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निदेशक ने प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने पर विभाग के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने 'ऑपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत बच्चों से बातचीत की

शिमला/शैल। भारतीय सेना की राष्ट्रीय एकता यात्रा 'ऑपरेशन

सद्भावना' के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के गुज्जर और बकरवाल समुदायों के 25 बच्चों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की।

राज्यपाल ने बच्चों के साथ बातचीत में कहा कि दूर-दराज एवं सीमांत क्षेत्रों के बच्चों के लिए इस प्रकार की शैक्षिक यात्राएं आयोजित करने की भारतीय सेना की पहल सराहनीय है। इस प्रकार की पहल राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बच्चों को देश की विविधता एवं विकास के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने बच्चों को लगन से शिक्षा ग्रहण करने और देश की प्रगति में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

यह यात्रा ममून कैंटोनमेंट से प्रारंभ हुई थी इस दौरान बच्चों ने पंजाब और हरियाणा राज्य के राज्यपाल से भेंट की तथा वेस्टर्न कमांड मुख्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने रॉक गार्डन और सुखना लेक जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया।

यात्रा के अंतिम चरण में बच्चे शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने अन्नाडेल म्यूजियम, बर्ड सैंक्चुरी, इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज और आर्मी ट्रेनिंग कमांड का भ्रमण किया तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भेंट की।

बच्चों ने भारतीय सेना का एक यादगार और ज्ञानवर्धक अनुभव का अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्यपाल का भी उनके प्रेरणादायक शब्दों और आत्मीय स्वागत के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा और यात्रा के समन्वयक लेफ्टिनेंट कर्नल अमरीक सिंह भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित विकासात्मक परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरे करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर अपने विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को

इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि अब से मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे।

सुक्खू ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने-अपने कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तीव्रता से कार्य करें। उन्होंने सभी विभागों की अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को गति प्रदान की जाए और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के कार्य में भी गति लाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

सुक्खू ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने और उनके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित करने को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफआरए और एफसीए के मामलों की स्वीकृति में तेजी लाई जाए और सभी विभाग अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि गांवों में रहने वालों के हाथों में पैसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूध के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, साथ ही प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय का मुख्य जरिया बन सकती है तथा कृषि विभाग इस दिशा में गम्भीरता के साथ कार्य करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की तरह ही इस वर्ष भी मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है। लेकिन राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर प्रभावित के जख्मों पर मरहम लगा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने राजस्व विभाग को इस वर्ष आपदा के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए ताकि यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द भेजी जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत तथा ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने जाखू में किया रावण दहन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को दशहरा के शुभ अवसर पर श्री

हनुमान मंदिर जाखू में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों को राज्य का भ्रमण और निवेश करने का दिया आमंत्रण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कनाडा के ओटावा स्थित ऐतिहासिक संसद हिल पर आयोजित कुल्लू दशहरा के भव्य समारोह के अवसर पर एक विशेष वीडियो

इस उत्सव में हिमाचल प्रदेश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध हिमाचली लोकनृत्य 'नाटी', पारंपरिक रामलीला का मंचन और सभी अतिथियों

संदेश के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। यह आयोजन सांसद मैरी-फांस लालोंडे द्वारा आयोजित किया गया और हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन एचपीजीए द्वारा इसका संयोजन किया गया।

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस अवसर पर हिमाचल की समृद्ध संस्कृति के जीवंत रंग पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित होंगे, जिससे विदेश में रह रहे लोगों को भी अपने घर जैसा अनुभव मिलेगा। विदेशों में रह रहे सभी हिमाचली हमारे राज्य के सच्चे ब्रांड एंबेसडर हैं। मैं कनाडा में रह रहे सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश आने और यहां निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए आमंत्रित करता हूं।'

को परोसी गई हिमाचली धाम मुख्य आकर्षण रहे।

इस आयोजन में 35 से अधिक क्षेत्रीय सामुदायिक संगठनों ने भाग लिया, जो कि हिमाचली प्रवासियों की एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। एचपीजीए की ओर से सह-संस्थापक भाग्य चंदर, अरुण चौहान और विवेक नज्ज़र ने प्रेरणादायक संदेश भेजने और वैश्विक मंच पर हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने में निरंतर सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर भारत के कनाडा स्थित उप उच्चायुक्त, वरिष्ठ राजनयिक, सामुदायिक नेता तथा अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

दिल्ली में रहने वाले हिमाचली लोगों से मातृभूमि की सेवा करने का आग्रह किया:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली में सायर महोत्सव और मंडी जन कल्याण सभा के 64वें वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की उच्च परम्पराओं को जीवित रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समृद्ध संस्कृति व परम्पराएं हमारी पहचान है। युवा पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस विरासत को संजोकर रख सकें। उन्होंने कहा कि सायर महोत्सव हिमाचलवासियों का एक महत्वपूर्ण समारोह है जिसे फसल काटने के पश्चात हर्षोल्लास से मनाया जाता है।

शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले हिमाचली लोगों से प्रदेशवासियों की सहायता करने का आग्रह किया और कहा कि यह उनकी ओर से मातृभूमि की सच्ची सेवा होगी। उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़े रहने और परम्पराओं को जीवित रखने का भी आग्रह किया।

उन्होंने हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जल्द ही 100 स्कूलों को सीबीएसई आधारित संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में इन सुधारों के कारण, अगले दो-तीन वर्षों में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा।

उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभा के लिए एक लाख रुपये की घोषणा की।

उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया।

मंडी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष के.आर. वर्मा ने जिला मंडी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभा द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक और मानवीय गतिविधियों से अवगत करवाया।

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग और जिला मंडी जन कल्याण सभा के सदस्य इस समारोह में शामिल हुए।

प्रदेश सरकार ने किसानों से खरीदा प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित 2,123 क्विंटल गेहूं 8 अक्तूबर से शुरू करेगी जौ की खरीद

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार 8 अक्तूबर से पांगी में प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ की खरीद शुरू करेगी, इससे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा खरीद की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभी तक इस घाटी में हुड़ान, सेचु, सुराल, किलाड़ और साच में पांच खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। पांगी क्षेत्र के 80 किसानों ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग में पंजीकरण करवाया है।

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद पूरे प्रदेश में पूरी कर ली गई है। 22 खरीद केंद्रों पर 838 किसानों से कुल 2,123.587 क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। गेहूं को आटे और दलिया में संसाधित किया जा रहा है और 'हिम-भोग' ब्रांड के तहत इसकी बिक्री की जाएगी।

किसानों को उनकी फसल के लिए 1.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त 4.15 लाख रुपये का भुगतान परिवहन सब्सिडी के रूप में किया गया है।

इसी के तहत गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का के लिए 40 रुपये, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये और जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। यह पहल उपभोक्ताओं के लिए न केवल रसायन मुक्त उत्पाद बल्कि प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमत भी प्राप्त हो रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीणों के हाथों में सीधे पैसा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र से दो नई पहल दुग्ध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना शुरू की हैं। दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि और परिवहन अनुदान योजना के तहत निजी दुग्ध समितियों को भी दूध संग्रहण और परिवहन के लिए 3 रुपये प्रति लीटर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकारी पॉलिटेक्निक, हमीरपुर में 9 अक्तूबर को आयोजित होगी ओवरसीज भर्ती ड्राइव

शिमला/शैल। राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर में 9 अक्तूबर, 2025 को सरकारी पॉलिटेक्निक, हमीरपुर में एक विशेष ओवरसीज भर्ती ड्राइव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचपीएसईडीसी) द्वारा श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ड्राइव के माध्यम से तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

विदेश मंत्रालय और पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

पंजीकरण, पात्रता मानदंड तथा आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी शीघ्र ही रोजगार कार्यालयों, उनकी सोशल मीडिया पेजों तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

आपको मानवता पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है अगर महासागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो महासागर गंदा नहीं हो जाता। ......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

भाजपा के राजनीतिक चरित्र पर उठते सवाल

जब सत्तारूढ़ सरकारें जनता का विश्वास खो देती हैं तब ऐसी स्थिति एक जनान्दोलन की शक्ल ले लेती है। किसी भी सरकार को परखने समझने के लिये दस वर्ष का समय बहुत होता है। क्योंकि इतने समय में उसकी वैचारिक समझ के बारे में पूरा खुलासा सामने आ जाता है। सरकार की वैचारिक समझ और नीयत पर जब कोई बुनियादी सवाल खड़े कर देता है और उन सवालों पर जब सरकारों की प्रतिक्रियाएं वैचारिक न रहकर केवल सतही हो जाती है तब अविश्वास और गहरा जाता है। आज देश में केन्द्र से लेकर राज्यों तक सभी सरकारें इस अविश्वास में घिर चुकी हैं। विपक्षी दलों की राज्य सरकारें केन्द्र पर उनके साथ असहयोगी भेदभाव बरतने का आरोप लगा रही हैं। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और अधिकांश राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं इसलिये भाजपा के राजनीतिक चरित्र पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। भाजपा संघ परिवार की एक राजनीतिक इकाई है जो जनसंघ से जनता पार्टी में विलय के बाद 1980 में पैदा हुई। वैसे संघ परिवार के 1948 और 1949 में गठित हुए विद्यार्थी परिषद और हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी शायद सबसे पुराने अनुसांगिक संगठन हैं। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार जनसंघ घटक के सदस्यों की आरएसएस के साथ भी सक्रियता रखने के कारण दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर टूटी थी। उसके बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार में भाजपा भागीदार थी। लेकिन मण्डल आयोग की सिफारिशें केन्द्र द्वारा लागू करने के मुद्दे पर भाजपा की वीपी सिंह सरकार के विरोध में खड़ी हो गयी। मण्डल के विरोध में कमण्डल खड़ा हो गया। मण्डल आयोग के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले 27 % आरक्षण का विरोध कमण्डल आन्दोलन ने किया। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के विरोध में खड़े हुए आन्दोलन में आत्मदाह तक हुए। शिमला में भी आत्मदाह की घटनाएं घटी हैं। परिणाम स्वरुप केन्द्र में सरकार गिर गयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तीन बार भाजपा नीत सरकारें तेरह दिन तेरह माह और फिर एक टर्म के लिये बनी। 2004 से 2014 तक केन्द्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार दो टर्म के लिये रही।

डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भाजपा/संघ प्रायोजित अन्ना और रामदेव के आन्दोलन आये। इन आन्दोलनों में भ्रष्टाचार और काले धन के भरोसे गये आंकड़ों ने आग में घी का काम किया। 2G स्पेक्ट्रम पर सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट आयी जिसमें 1,76,000 करोड़ का घपला होने का आरोप लगा। इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का मुद्दा जुड़ गया। बाबा रामदेव ने काले धन के लाखों करोड़ के आंकड़े परोसे। लोकपाल की मांग इस आन्दोलन की केन्द्रीय मांग बन गयी। भ्रष्टाचार और काले धन के आंकड़े के प्रचार प्रसार में केन्द्र में सरकार बदल गयी। 2014 में कांग्रेस और अन्य दलों से बड़ी संख्या में नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन भ्रष्टाचार और काले धन के आरोपों पर क्या जांच हुई यह आज तक सामने नहीं आया है। जबकि विनोद राय का अदालत में यह बयान सामने आया है कि उन्हे गणना करने में चूक हो गई थी और कोई खपला नहीं हुआ है। कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में हुये घपले के आरोप में भी क्लीन चिट मिल गयी है। काले धन का आंकड़ा पहले से दो गुना हो गया है। लोकपाल में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला गया हो ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया है।

इस सरकार ने 2014 और 2019 के चुनाव में जो वायदे किये थे वह कितने पूर्व हुये हैं? दो करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा कितना पूरा हुआ है? महंगाई 2014 के मुकाबले आज कहां खड़ी है? इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जबकि देश में इन दस वर्षों में दो बार नोटबन्दी हो चुकी है। सरकार ने सभी कमाई वाले सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट सैक्टर को थमा दिया है। इस सरकार ने कोई बड़ा संस्थान खोला हो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है जबकि कर्जदारों की सूची में भारत विश्व बैंक में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज देश को हिन्दू-मुस्लिम के मतभेद और ई.डी. सी.बी.आई. और आयकर जैसी एजेन्सियों के डर से चलाया जा रहा है। जिस लोकप्रिय मतदान से इस सरकार के बनने का दावा आज तक किया जाता रहा है उस दावे की हवा राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने पूरी तरह से हवा निकाल दी है। आज प्रधानमंत्री स्वयं व्यक्तिगत आरोपों में घिरते जा रहे हैं। पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर स्व घोषित सिद्धांत पर भाजपा को ही पूर्वरिष्ठ नेतृत्व जिस तर्ज में सवाल दागने लग गया है उसके परिणाम भयानक होंगे। इन्हीं कारणों से आज भाजपा अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। आज भाजपा के राजनीतिक चरित्र पर उठते सवाल उसके आकार से ही बड़े होते जा रहे हैं। इन सवालों से ज्यादा देर तक बच पाना आसान नहीं होगा।

वांगचूक के आन्दोलन को गंभिरता से लें, अन्यथा इसका असर पूरे पश्चिमोत्तर भारत पर पड़ेगा

गौतम चौधरी

अभी भारत के कुछ उत्साही हिन्दू राष्ट्रवादी, नेपाल के 'जेन जी रेवॉल्यूशन' का जश्न मना कर आराम ही कर रहे थे कि लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आयी। खबर यह है कि केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ उत्साही युवाओं ने देश के सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। आन्दोलन अभी भी जारी है और केन्द्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि वहां के आन्दोलन को शांत करने के लिए अब केन्द्रीय सुरक्षा बल एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। मतलब साफ है कि अब भारत का एक और शांत राज्य अशांति का दंश झेलने को अभिशप्त है। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस अशाति का हेतु क्या है? ऐसे कई प्रश्न है, जो कूटनीतिक क्षितिज पर तैर रहे हैं और लगातार जवाब ढूंढ रहे हैं।

पहले तो लद्दाख की हालिया स्थिति क्या है, उस पर चर्चा करना ठीक रहेगा। मसलन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा देने की मांग को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन एकाएक हिंसक हो गया और भीड़ ने लेह में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। बता दें, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और उन्हीं मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन था। उन्होंने समाचार माध्यमों को बताया कि लेह में आज हुई हिंसा के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की है। मिल रही जानकारी में बताया गया है कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। कुछ वीडियो में कई वाहन जलते हुए दिख रहे हैं और कुछ झड़पें भी हुई हैं। स्थानीय समाचार के अनुसार फिलहाल लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने सोनम वांगचुक पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। हिंसा के बाद ही सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने कहा, "आज, हमारे भूख हड़ताल का 15वां दिन था। लेह सिटी में व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से मैं दुखी हूं। कई कार्यालयों और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। पांच सालों से (युवा) बेरोज़गार हैं। एक के बाद एक बहाना करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और लद्दाख को भी संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस हिंसा में तीन से पांच युवाओं की जान जाना दुखद है और हम उनके परिवारों के साथ शोक जताते हैं।" इसका मतलब साफ है कि इस हिंसक आन्दोलन में कुछ लोगों की जान भी गयी है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान लोगों के मारे जाने के बारे में पुलिस प्रशासन ने कोई बयान जारी नहीं किया है।

इस क्षेत्र के लोगों की थोड़ी पीड़ा भी समझनी होगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गैज़ेटेड पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो गया है। वर्ष 2019 से पहले नॉन गैज़ेटेड नौकरियों के लिए जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड भर्ती करता था और उस में लद्दाख के उम्मीदवार भी होते थे लेकिन अब ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही हैं। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार के लिए भर्तियां करता है। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से लेकर आजतक लद्दाख में बड़े स्तर पर नौकरियों के लिए नॉन-गैज़ेटेड भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर लद्दाख के युवाओं में गुसा है। लद्दाख के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ-साथ लद्दाख को विधानमंडल भी दिया जाएगा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा भी संभव नहीं हो पाया है। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इन वादों से मुकर रही है और इस असंतोष ने प्रदर्शन का रूप ले लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है।

लद्दाख की घटना से केवल लेह-लद्दाख वाले क्षेत्र पर ही असर नहीं होगा। इसका असर पूरे पश्चिमोत्तर पहाड़ी राज्यों पर पड़ने की संभावना है। सोनम वांगचुक को उत्तराखंड में भी बड़ी स्वीकार्यता मिल रही है। लगभग एक वर्ष पहले उत्तराखंड एकता मंच के कुछ प्रतिनिधियों ने सोनम से जाकर मुलाकात की थी। इसी वर्ष यानी 2025 में बीते 21 मई को वांगचुक उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी देहरादून आए थे। उस दौरान उन्होंने जो बातें कही वह अहम है और इससे केन्द्र सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। देहरादून के अपने भाषण में वांगचुक ने कहा, "केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था, तब लोगों को लगा कि लद्दाख का विकास होगा। इस उम्मीद के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया। लेकिन जब केंद्र शासित राज्य बनाने का जश्न खत्म हुआ, तब पता चला कि यह तो लद्दाख के लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि अब इस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में नहीं होगा।" उन्होंने कहा, "यह व्यवस्था संभवत इसलिए की गई ताकि कॉरपोरेट द्वारा संचालित परियोजनाएं बिना स्थानीय लोगों की सहमति के बनाई जा सकें। उनका कहना था कि उत्तराखंड सहित सभी पहाड़ी राज्यों में विकास कॉरपोरेट के दबाव में किया जा रहा है। लद्दाख की जनता छठी अनसूची की मांग कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना कोई परियोजना लद्दाख में न बने।" इधर उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तरह पांचवी अनुसूची की मांग हो रही है। जिसके तहत पेसा कानून लागू होता है। यहां यह भी बता दें कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले भाजपा के नेता पंडित मनोहर कांत ध्यानी पहाड़ी राज्यों का एक परिसंघ बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। यहा योजना पंडित जी की खुद की नहीं थी। इस योजना के पीछे कई बड़ी शक्तियां काम कर रही थी। यहां भाजपा के रणनीतिकारों को भी पता होगा। खैर राज्य बनने के बाद यह मुद्दा गौन पड़ गया लेकिन याद रहे उत्तराखंड में फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है। उन तमाम जानकारियों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है।

वांगचूक का संदेश साफ है कि हम कॉरपोरेट की लूट को अपने यहां खुली छूट नहीं देंगे। दूसरा वे अन्य पहाड़ी राज्यों को भी अपने आन्दोलन के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर पश्चिमोत्तर भारत के ये पहाड़ी राज्य अशांत हो गए तो यह भारत की उत्तरी सीमा के लिए खतरनाक साबित होगा। इधर नेपाल में लगातार उपद्रव जारी है। नेपाल के उपद्रव में किन शक्तियों का हाथ है यह तो बताना थोड़ा कठिन है लेकिन नेपाल का अशांत होना भारत के हित में कतई नहीं है। भूटान को लेकर भी भारत पूर्ण रूप से आस्वस्थ नहीं हो सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अस्थाई शांति है। कब यह क्षेत्र अशांत हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वांगचूक के कुछ जायज मांगों पर केन्द्र सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। साथ ही पहाड़ी राज्यों में उठ रहे असंतोष को यथाशीघ्र समाधान की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह खतरा पैदा कर सकता है।

मोटापे और कुपोषण से सीधे निपटना: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 रणनीति

– श्रीमती अन्नपूर्णा देवी –
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

2018 में, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत के पोषण परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में पोषण अभियान शुरू किया गया था। महिलाओं और बच्चों के पोषण एवं कल्याण पर केंद्रित यह मिशन, भारत की कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक विकासशील भारत के निर्माण हेतु प्रतिबद्धता है- एक ऐसा भारत जो स्वस्थ, सशक्त और समावेशी हो।'विकसित भारत@2047' की यात्रा में पोषण अभियान एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पित है- एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा सुपोषित हो, हर मां सशक्त हो, और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

जब एक बच्चा सही पोषण पाता है, अच्छी तरह सीखता है और मजबूती से बढ़ता है- तो हम केवल एक जीवन नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की दिशा बदलते हैं। बच्चों को पर्याप्त पोषण, शिक्षा और सामुदायिक देखभाल प्रदान करके हम एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में निवेश कर रहे हैं- विकसित भारत के भावी नेतृत्व को आकार दे रहे हैं। एक स्वस्थ बच्चा केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की चिंगारी है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से मंत्रालय बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण परिणामों को बेहतर बनाने हेतु एक समन्वित तंत्र विकसित कर रहा है। इस अभियान का केंद्र है, देशभर में फैले 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का विशाल नेटवर्क, जो लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान कर रहा है। यद्यपि इसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएं और 23 लाख से अधिक किशोरियां शामिल हैं, लेकिन लाभार्थियों में से अधिकांश 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'एक समय पर एक भोजन' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए 8 करोड़ से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के ज़रिए, भविष्य को पोषित कर रहा है। इस प्रयास का मूल है- पूरक पोषण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और सभी लाभार्थियों को पौष्टिक टेक होम राशन प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए और औसत दैनिक सेवन एडीआई के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है। हम विविध आहार को अपनाते हुए स्थानीय, मौसमी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे श्री अन्न- जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू आदि को बढ़ावा देकर-हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने, बढ़ने और फलने-फूलने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिले।

जहां हमने बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्याओं से निपटने में प्रगति की है, वहीं अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण पोषण संकेतक- अधिक वजन और मोटापे की समस्या को भी दूर करने की दिशा में अग्रसर हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बचपन में मोटापा बच्चों के वयस्क होने पर उनके लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिससे टाइप-2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे और अधिक वजन के मनोवैज्ञानिक परिणाम भी हो सकते हैं, जो स्कूल के प्रदर्शन और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, और बढ़ते भेदभाव और कलंक के कारण यह स्थिति और भी बदतर हो जाती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफ़ोर्निया द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया बर्कले और मैकगिल के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को गर्भावस्था के दौरान गर्भ में रहते हुए भी, अपने पहले 1,000 दिनों के दौरान चीनी सेवन पर नियंत्रण लगाया गया, उनमें वयस्क होने पर टाइप 2 मधुमेह होने का जोखिम 35 प्रतिशत तक कम और उच्च रक्तचाप होने का जोखिम 20 प्रतिशत तक कम हो गया।

यह दर्शाता है कि गर्भवती मां का चीनी सेवन भी बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।

इस समस्या के समाधान और पूरक पोषण की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरक पोषण की संरचना के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) की सिफारिशों के अनुरूप है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों के अनुसार, वयस्कों और बच्चों, दोनों के लिए चीनी का सेवन कुल दैनिक ऊर्जा सेवन के 10 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। WHO दैनिक ऊर्जा सेवन में अधिमुक्त शर्करा की मात्रा को और (Sugars) घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की 2024 के आहार दिशानिर्देशों के अनुसार, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई अतिरिक्त चीनी नहीं दी जानी चाहिए और गर्भवती महिलाओं सहित सभी आयु व जेंडर समूहों के लिए चीनी का सेवन 5 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

अधिमुक्त शर्करा बच्चों में दंत क्षय (Cavities) और दांतों की सड़न -का एक प्रमुख कारण भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह दंत क्षय कैविटी को बढ़ाने में एक आवश्यक आहार कारक है। चीनी सेवन को सीमित करने से बच्चों में दांतों की सड़न और क्षय को कम किया जा सकता है।

हमारे मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि परिष्कृत चीनी का उपयोग सीमित किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर गुड़ या अन्य प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करें, और इसे कुल ऊर्जा सेवन के 5 प्रतिशत से कम तक सीमित रखें। हमने अनुरोध किया है कि पूरक पोषण में नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुबह के नाश्ते और स्वास्थ्य वर्धक आहार में मिठास वाले व्यंजनों की संख्या भी घटाने का आग्रह किया गया है।

हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे THR व्यंजन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनमें अतिरिक्त नमक और चीनी न हो, जिससे लाभार्थी अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार स्वाद बदल सकें। सभी आयु समूहों में वसा, नमक और चीनी(HFSS) की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी हतोत्साहित किया गया है। खाद्य गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि सामग्री को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 का पालन करना चाहिए और शिशु आहार खाद्य सुरक्षा और मानक शिशु पोषण हेतु खाद्य विनियम, 2020 का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त चीनी को 'ना' कहकर, भारत मोटापे, उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी रोकथाम योग्य बीमारियों से मुक्त भविष्य के लिए 'हां' कह रहा है।

जहां पारंपरिक खाद्य पदार्थ बाज़ार में लोकप्रिय हो रहे हैं, वहीं मंत्रालय पहले से ही 'पुष्टाहार'- स्थानीय, मौसमी सामग्री और अनाज जैसे रागी, बाजरा, टुकड़ा गेहूं, चना और फोर्टिफाइड चावल से बने पौष्टिक प्रीमिक्स प्रदान कर रहा है। ये मिश्रण- स्वाद और पोषण दोनों में समृद्ध हैं, जिन्हें स्थानीय स्वादानुसार मीठे या नमकीन रूप में तैयार किया जा सकता है। पुष्टाहार, दुकानों से खरीदे जाने वाले मिश्रणों का एक स्वास्थ्यवर्धक और अधिक बहुमुखी विकल्प है, जो स्थानीय, मौसमी स्वाद और संपूर्ण पोषण प्रदान करता है।

जैसे-जैसे हम अपने नागरिकों को पर्याप्त कैलोरी प्रदान करके सुपोषित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों और महिलाओं को जो भोजन दिया जा रहा है,उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों, जो हमारे देश का भविष्य हैं, को जो भोजन प्रदान करते हैं, वह उनके समग्र विकास और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अपने खान-पान की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके हम अपने भविष्य को अधिक मजबूत, स्वस्थ और रोग-मुक्त बना सकते हैं। इस अमृत काल में, हमारे बच्चों को पौष्टिक भोजन और पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध होनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए भोजन न केवल पर्याप्त होना चाहिए, बल्कि पौष्टिक भी होना चाहिए, जो उनके समग्र विकास और वृद्धि में योगदान दे।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना से आत्मनिर्भर हो रहे युवा

ई-टैक्सी पर 50 फीसदी उपदान

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोल रही है। योजना के तहत ई-टैक्सी के लिए पात्र युवाओं को 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। साथ ही सरकारी विभागों से संबद्ध कर गाड़ी किराए पर देने का प्रावधान भी किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनमें उद्यमशीलता की भावना विकसित करना है। ई-टैक्सी की यह पहल राज्य सरकार के सहयोग से युवाओं को स्थायी आय का एक सशक्त माध्यम सुनिश्चित करती है। पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत तक उपदान देती है। शेष राशि में लगभग 40 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है और केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी लाभार्थी को स्वयं वहन करनी पड़ती है।

योजना के तहत खरीदी गई ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ संबद्ध किया जाता है, जिससे लाभार्थियों को प्रति माह सरकार द्वारा ई-टैक्सी के अनुसार 50 से 60 हजार रुपये दिए जाते हैं। योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, वैध ड्राईविंग लाइसेंस धारक और पात्र आयु सीमा वाले युवाओं को ही मिलेगा।

नेचुरल एवं ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की इस अभिनव पहल के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ा है। प्रदेश में इस योजना के तहत गत वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत मंडी जिला में भी अब तक लगभग 21 लाख 74 हजार रुपए का उपदान लाभार्थियों को प्रदान किया जा चुका है।

योजना के लाभार्थी मांडल गांव के मुकेश ठाकुर ने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप ई-टैक्सी योजना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। इसके उपरांत फार्म भरा और साक्षात्कार दिया। ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद उन्हें ई-टैक्सी मिल गई। उन्होंने बताया कि उनकी यह ई-टैक्सी जल शक्ति विभाग से संबद्ध की गई है।

मुकेश ठाकुर ने बताया कि इससे पहले वे चालक की नौकरी करते थे और मात्र 10 हजार रुपए वेतन मिलता था। इससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। उन्होंने बताया कि ई-टैक्सी योजना के तहत उन्होंने लगभग साढ़े 15 लाख रुपये की गाड़ी खरीदी जिस पर साढ़े सात लाख रुपए सब्सिडी 50 प्रतिशत की दर से मिल चुकी है। जल शक्ति विभाग से संबद्ध होने के बाद अब हर महीने 50 हजार रुपये मिलते हैं। इस योजना से उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है तथा घर का खर्चा भी आसानी से चल रहा है। सरकार द्वारा इस तरह की योजना चलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया है।

तहसील संधोल के भूर गांव निवासी सुभाष चंद्र भी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के लाभार्थी हैं। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली है। आजकल उनकी गाड़ी जल शक्ति विभाग पधर उपमंडल में लगी है। उन्होंने बताया कि हर माह 50 हजार रुपये की आय हो रही है। पहले वह बेरोजगार थे, लेकिन इस योजना का लाभ उठाकर अब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से भी अपील की है कि सरकार की ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वे भी स्वरोजगार की राह अपना सकते हैं। सुभाष ने इसके लिए प्रदेश सरकार और विशेषतौर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी की पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील पत्थर साबित हो रही है। इससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्थिर आय का साधन मिलने से उनकी आर्थिकी में सुधार हो रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से वातावरण स्वच्छ रखने में भी मदद मिल रही है।

ई-केवाईसी होने से पात्र परिवारों को मिल रहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ

मार्च, 2025 तक 97 फीसदी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण

तकनीक के जरिए दक्षतापूर्ण और पारदर्शी बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को अपनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और अधिक दक्षतापूर्ण और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आधार कार्ड नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले।

ई-केवाईसी होने से फर्जी या अपात्र लोगों को पीडीएस से बाहर करने और पात्र परिवारों को सब्सिडी युक्त अनाज और अन्य लाभ पहुंचाने में मदद मिल रही है। ई-केवाईसी प्रक्रिया मई, 2022 में शुरू हुई और पूरे प्रदेश में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में इसकी अहम भूमिका है। मई, 2022 से जनवरी, 2023 तक, करीब 60 फीसदी पीडीएस लाभार्थियों ने उचित मूल्य की दुकानों पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाई।

प्रदेश के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने खुद का ई-केवाईसी एप्लिकेशन जुलाई, 2023 में लॉन्च किया। इससे लाभार्थियों के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर आधार द्वारा फिंगरप्रिंट सत्यापन का इस्तेमाल करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना सुगम हो गया।

जुलाई, 2023 से जुलाई, 2024 तक ई-केवाईसी करवाने वालों की संख्या 77 फीसदी हो गई। हालांकि, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों को उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचने में असुविधा या सत्यापन के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की, ताकि लाभार्थी आधार द्वारा चेहरे की पहचान के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकें। इससे दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के लिए यह प्रक्रिया सरल हो गई क्योंकि उन्हें अब उचित मूल्य की दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं रही। चेहरे से सत्यापन की सुविधा शुरू होने से ई-केवाईसी की दर जुलाई, 2024 में 77 फीसदी से बढ़कर मार्च, 2025 तक 97 फीसदी हो गई है।

आधार सत्यापन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया है। इससे पात्र परिवारों की पहचान हुई, साथ ही प्रतिलिपिकरण डुप्लीकेशन को हटाने और प्रक्रिया को गतिशील व अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिली। ई-केवाईसी और चेहरे से सत्यापन की सफलता दर्शाती है कि तकनीक के माध्यम से हर संसाधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने छः अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने

अधिकारिक आवास 'ओक ओवर' शिमला से छः अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में ये वैन तीन जिला फोरेंसिक इकाइयों बद्दी, नूरपुर और बिलासपुर, जुन्गा स्थित राज्य फोरेंसिक लैब और धर्मशाला व मंडी स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में तैनात की जाएंगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह, संरक्षण और भंडारण जांच अधिकारियों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए मानक दिशा-निर्देश नामक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को भी लॉन्च किया तथा आपराधिक घटना स्थल का निरीक्षण करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए जैकेट का अनावरण किया।

उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक वाहनों का उपयोग जांचकर्ताओं द्वारा अपराधिक स्थल पर साक्ष्य इकत्र करने के लिए किया जाएगा। इससे कुशल, त्वरित तथा निपुणता से साक्ष्य का संरक्षण और वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण और संग्रहण किया जाएगा। फोरेंसिक जांच को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इससे सजा की दर में सुधार होगा और न्याय प्रणाली मजबूत होगी।

प्रत्येक वाहन की कीमत 65 लाख रुपये है और यह वैन, किट और ड्रग तथा विस्फोटक पहचान प्रणाली, फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट डवेल्पमेंट किट्स, डीएनए सैंपलिंग किट्स, एरोजन किट, रेफ्रिजरेशन यूनिटस, पोर्टेबल पावर जनरेटर, साइबर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर, उच्च रेजोल्यूशन वीडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रणाली, माइक्रोस्कोप, जीपीएस के साथ बड़े वार्न कैमरा, डीएसएलआर कैमरा, सीसीटीवी फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ व्हीकल और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस है।

उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ इंटेग्रेटिड किट में उपलब्ध लेटेंट फिंगरप्रिंट, जैविक तरल पदार्थ, बाल, कपड़ा फाइबर, गोली और विस्फोटक अवशेष, काटने के निशान, संदिग्ध दस्तावेज, टायर के निशान, जूते के निशान, नशीले पदार्थ और अन्य ट्रेस साक्ष्य से जांच को प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। इन मोबाइल प्रयोगशालाओं का एक प्राथमिक उद्देश्य फोरेंसिक साक्ष्यों का तत्काल और दोषमुक्त संग्रह सुनिश्चित करना है, क्योंकि देरी से साक्ष्यों को एकत्रित करने से जांच प्रक्रिया बाधित होती है।

उन्होंने कहा कि यह पहल सबूत इकत्र करने में अधिक पारदर्शिता और अपराध को साबित करने की प्रक्रिया को तेज करेगी। वर्तमान में बदलते आपराधिक मामलों के अनुरूप जांच तंत्र को भी उन्नत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल फोरेंसिक सेवाओं में तेजी लाएगी, बल्कि सटीक, विश्वसनीय साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित करके अपराध सिद्ध करने में भी बढ़ावा देगी।

उन्होंने कहा कि फोरेंसिक सेवा निदेशालय अब न केवल राज्य जांच एजेंसियों, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में मदद करता है।

हिमाचल प्रदेश के लिए दो नए केंद्रीय विद्यालय मंजूरः शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल समिति ने पूरे देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनमें हिमाचल प्रदेश के लिए भी दो नए केन्द्रीय विद्यालय कम होगी।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में लगभग 80 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, विद्यालयों के निर्माण और संबंधित कार्यों से श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर

शामिल किए गए हैं। ये विद्यालय जिला शिमला के कोटखाई और जिला सिरमौर के पांवटा-साहिब में खोले जाएंगे।

रोहित ठाकुर ने बताया कि यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार की सिफारिश और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप लिया गया है। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, जो राज्य सरकार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रति मजबूत संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि ये नए विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत प्री-प्राइमरी स्तर से शिक्षा प्रदान करेंगे। इस निर्णय से राज्य के हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं के निकटतम विकल्प सुनिश्चित होंगे और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को अन्य स्थानों पर पलायन की आवश्यकता भी भी सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार की मांग और सिफारिशों को समर्थन प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने की दिशा में इसी तरह अपने प्रयास जारी रखेगी, ताकि प्रदेश को और अधिक केंद्रीय संस्थान स्वीकृत हो सकें और प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतरीन अवसर मिल सकें।

उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में ये प्रयास और व्यवस्था परिवर्तन के तहत सुधार हिमाचल प्रदेश को ज्ञान का हब बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित होती है।

रिवर्स बायरसेलर मीट में भाग लेने के लिए हांगकांग के उद्योगपतियों को हिमाचल का निमंत्रण

शिमला/शैल। हांगकांग स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल और हांगकांग के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों एवं निवेशकों के बीच एक संवादात्मक व्यवसायिक सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह सहभागिता हिमाचल

प्रदेश और हांगकांग के बीच औद्योगिक सहयोग, व्यापारिक संबंधों और निवेश साझेदारियों को विस्तारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय उद्योग मंत्री, हर्षवर्धन चौहान ने किया। उनके साथ आर.डी. नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, हिमाचल प्रदेश सरकार, तिलक राज शर्मा, अतिरिक्त निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा संजय शर्मा, हिमाचल उद्योगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हांगकांग में भारत की कार्यवाहक महा वाणिज्यदूत, सुश्री सुरभि गोयल ने किया, जिन्होंने राज्य की क्षेत्रवार साझेदारियों को प्रोत्साहित करने और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल ने आगामी रिवर्स बायरसेलर मीट की घोषणा करते हुए हांगकांग के व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश में व्यापारिक अवसरों की खोज के लिए भागीदारी का आमंत्रण दिया।

इस सत्र में भारत और हांगकांग के अनेक अग्रणी उद्योगपतियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थे। सुरेंद्र रोशा एच.एस. बी.सी., डॉ. प्रदीप हेटरो मेडिकल, गुल मिर्पुरी आई.बी.ए., सुश्री भारती मानेक आई.सी.सी., विपिन पाडे एस.बी.आई., दिलीप बरूआ एयर इंडिया, सुमित लाथ शार्ज़र, क्रिस्टोफर प्राइमार्क, एलेक्स कैसर सी.एल.पी., मनोज कुलकर्णी जॉनसन इलेक्ट्रिक्स, सुश्री उर्मिल जेस्वानी भगवती इंटरनेशनल, मोहित जेस्वानी भगवती इंटरनेशनल, महेंद्र गोकल गोकल एंड संस लिमिटेड और केन लाम जी-लॉग्स लिमिटेड। इन सभी ने हिमाचल प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रित चर्चाओं में भाग लिया।

बैठक के दौरान आर.डी. नजीम ने हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक स्थिति और निवेश-अनुकूल नीतियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने राज्य की विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि निर्माण, पर्यटन, प्रौद्योगिकी तथा विद्युत गतिशीलता में रणनीतिक विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक सहयोग से संचालित 'रैम्प (RAMP) कार्यक्रम' के अंतर्गत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साहसिक और आध्यात्मिक पर्यटन, विशेषकर 'बौद्ध परिपथ' के विकास की संभावनाओं को भी प्रमुखता दी।

सतत औद्योगिकीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने यह आश्वासन दिया कि निवेशकों को मजबूत एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से सुगम कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

यह संवादात्मक सत्र आपसी आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने, नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देने और उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने के सामूहिक संकल्प के साथ संपन्न हुआ।

हिमाचल को आधार फेस ऑथेंटिकेशन नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के अभिनव उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राज्य को यह पुरस्कार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आधार प्रमाणीकरण तकनीक को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनने पर प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पारदर्शी और कुशल, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटल समाधान लागू करने में हिमाचल प्रदेश की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित आधार दिवस समारोह के दौरान यूआईडीएआई की राष्ट्रीय पहल संवाद के अन्तर्गत प्रदान किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां उचित मूल्यों की दुकानों पर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित राशन वितरण आरंभ कर दिया गया है। यह समाधान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा (डीडीटीजी) डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलोजिज़ एंड गवर्नेंस विभाग और यूआईडीएआई के परामर्श से विकसित किया गया है। यह तकनीक किफायती, सरल और उच्च प्रमाणीकरण सफलता दर के साथ सुशासन को और अधिक मजबूत बनाती है।

उन्होंने बताया कि इस पहल से लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया सरल हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सक्षम और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब फिंगरप्रिंट और ओटीपी जैसे पुराने प्रमाणीकरण तरीकों से आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना शुरू की जाएगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस-2025 के अवसर पर आयोजित

राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजनों को उचित मान-सम्मान देने और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार 6 लाख 71 हजार 754 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 1000 से 1700 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी आय सीमा के प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि 60 से 69 वर्ष के पुरुषों को 1000 रुपये प्रतिमाह, 60 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 1700 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को भी प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्वालामुखी में 100 करोड़ रुपये की लागत से 'सुख आश्रय परिसर' का निर्माण किया जा रहा है, जहां वृद्धजनों को घर जैसा माहौल और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच हेतु रोगी मित्र योजना भी प्रारंभ की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला शिमला के यशपाल, केशव राम, सुमित्रा चन्देल, सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीनिवास जोशी, हीरानन्द शांडिल्य और नरेन्द्र कटारिया, सिरमौर के प्रो. अमर सिंह चौहान, राजेन्द्र कुमार शर्मा व विद्यानन्द सरैक, सोलन के डा. पी.के. पठानिया, हेल्प एज इण्डिया सोलन, सोलन निवासी शैलेन्द्र पंवर, हमीरपुर के मिलाप सिंह, कुल्लु की अनिता ठाकुर, बिलासपुर के मस्त राम वर्मा और जमनु राम, ऊना के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह और मण्डी के मनोहर लाल शर्मा को सम्मानित किया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने साइक्लिंग रैली और वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में 60 से 82 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रैंप वॉक किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

मुख्यमंत्री ने 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई

जल्द भरे जाएंगे 700 होम गार्ड पद: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान से 14 नए अग्निशमन

वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों की खरीद पर 6.70 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। ये वाहन जिला शिमला के प्रशिक्षण केंद्र बलदेयां, अग्निशमन केंद्र देहा, उबादेश, नेरवा और ठियोग, ज़िला मंडी के धर्मपुर और थुनाग, ज़िला लाहौल-स्पीति के काजा, जिला कांगड़ा के शाहपुर और इंदौरा तथा जिला हमीरपुर के नादौन अग्निशमन केंद्रों के लिए रवाना किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अग्निशमन वाहनों को दूरदराज और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैनात किया गया है, ताकि आग लगने की घटनाओं पर समय पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि बेड़े को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त अग्निशमन वाहनों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए और उन्नत अग्निशमन केंद्रों के उपकरणों के लिए 4.24 करोड़ रुपये और नादौन व इंदौरा में विभागीय भवनों के निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए 700 होम गार्ड की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

हिमाचल सेब और नाशपाती की खेती के लिए न्यूजीलैंड के साथ सहभागिता पर कर रहा विचार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च आयुक्त पैट्रिक जॉन राटा की अध्यक्षता में भेंट

की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र, विशेष कर सेब और नाशपाती की खेती, में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी विधियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किसानों के प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है। इस सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल उपरान्त प्रबंधन सुदृढ़ होगा और अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर हिमाचल के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ उच्च घनत्व बागवानी, बगीचों का प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, भंडारण और विपणन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में प्रदेश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इससे न केवल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि हिमाचल की बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले अढ़ाई वर्षों से इसी दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत से बागवानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं। न्यूजिलैंड की विशेषज्ञता के सहयोग से प्रदेश आधुनिक, सतत और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाकर सेब और नाशपाती की खेती में एक नए युग की शुरुआत करेगा।

इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने अर्की में 68.42 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में 68.42

करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 23.01 लाख रुपये की लागत से निर्मित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझयाट के परीक्षा हॉल, 3.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग के भवन के दूसरे चरण, 45.90 लाख रुपये की लागत से कृषि विस्तार कार्यालय, 2.23 करोड़ रुपये से निर्मित उप-कोषागार भवन दाड़लाघाट और 4.89 करोड़ रुपये की लागत से नव-निर्मित पुलिस स्टेशन भवन दाड़लाघाट का लोकार्पण किया।

उन्होंने नाबार्ड के अन्तर्गत 7.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मझयाट-पटी देवरा-पपलऊ सड़क, 1.35 करोड़ रुपये की लागत से जल शक्ति उप-मंडल अर्की के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं के सुधार व पुनर्गठन कार्य तथा 24.48 करोड़ रुपये की लागत से गम्भर खड्ड से अर्की क्षेत्र की आंशिक रूप से कवर बस्तियों तक उठाऊ पेयजल योजना के कार्य का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने 58.95 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले डुमैहर पशु चिकित्सालय भवन, अर्की नगर के लिए 18.50 करोड़ रुपये के पेयजल योजना सुधार कार्य, अर्की तहसील की ग्राम पंचायत सरैयांज और मटेरनी के लिए 2.32 करोड़ रुपये की लागत से जल वितरण प्रणाली के सुधारीकरण कार्य और दाड़लाघाट में 1.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय व सह-आवासीय भवन की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने क्षेत्र के लिए इन विकास परियोजना को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्य सचिव ने शीतकालीन तैयारियों और सड़क मरम्मत कार्यों की समीक्षा की

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्बहाली कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने शीतकालीन मौसम की तैयारियों के दृष्टिगत आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क मरम्मत कार्यों और विभिन्न तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया गया।

उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों को किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी हिस्सों में कम से कम दो लेन निरंतर खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। एनएचएआई के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि हाल की बरसात में राजमार्ग के उन हिस्सों जहां भारी क्षति हुई है, में भी दो लेन का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों को सर्दी का मौसम शुरू होने से पूर्व आवश्यक तैयारियां और इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बर्फ हटाने और अन्य आवश्यक उपायों की पूर्व योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि ठंड के महीनों में संपर्क सुविधा जारी रहे और लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों को मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि 120 प्रभावित सड़कों में से अधिकतर इस महीने के अंत तक बहाल हो सकें।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने अवगत करवाया कि विभाग मलबा प्रबन्धन के लिए उचित स्थानों को चिन्हित कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नई सड़कों के निर्माण की बजाय मौजूदा सड़कों को मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने तकनीकी सहायता के लिए आईआईटी रोपड़ से साझेदारी की है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी, कामकाज में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के दृष्टिगत जलवायु-प्रतिरोधी क्लाइमेट-रेजिलिएंट बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या बैंस के माध्यम से ई.डी. हिमाचल में कुछ बड़ा करने जा रही है?

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में ई.डी. के दखल से उठी चर्चा

शिमला/शैल। कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला का निदेशक मण्डल नाबार्ड और आर.बी.आई. की रिपोर्ट के बाद भंग कर दिया गया है। नाबार्ड ने पूरे निदेशक मण्डल के सदस्यों से जवाब तलबी की है। इसी बीच इस प्रकरण में ई.डी का दखल हो गया है। ई.डी. ने बैंक प्रबंधन से शिमला में पूछताछ की है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में सी.बी.आई. का भी दखल होने वाला है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बैंक के घोटाले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बैंक में जिस तरह का कामकाज पिछले आठ वर्षो से चल रहा था उसको देखते हुये सरकार ने निदेशक मण्डल को निलंबित कर दिया है। बैंक के निदेशक मण्डल के निलंबन का आधार नाबार्ड और आर.बी.आई. की विस्तृत रिपोर्ट बनी है। लेकिन मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से यह संदेश गया है कि इस सरकार के कार्यकाल में नियुक्त निदेशक मण्डल भी बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं ला पाया बल्कि उसी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाता रहा। प्रदेश के सरकारी बैंकों पर पंजीयक सहकारी सभाओं के माध्यम से सरकार का पूरा नियंत्रण है और इसी नियंत्रण के माध्यम से सहकारी बैंकों को सहकारिता विभाग से निकाल कर वित्त विभाग के अधीन ला दिया गया और वित्त विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के अपने पास हैं। बैंक किसी को भी कोई भी राहत ऋण के मामले में ओ.टी. एस. योजना के तहत ही दे सकता है। इस परिदृश्य में इन दिनों जिस तरह से 45 करोड़ के ऋण को 21 करोड़ में सेटल करने का प्रकरण चर्चा में आया है और बैंक में ई.डी. का दखल हो गया है उससे इस मामले ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है।

स्मरणीय है कि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला बैंस प्रकरण के कारण चर्चा में आया और इस समय प्रदेश का सबसे गंभीर मुद्दा बन चुका है। जिसका राजनीतिक प्रतिफल बहुत गंभीर होने के संकेत बाहर आते जा रहे हैं। क्योंकि यह चर्चा तब उठी जब बैंस ने एक पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया कि उसने ई.डी. में शिकायत दर्ज करवाई है और इस शिकायत के आधार पर ई.डी. ने नादौन और हमीरपुर में छापेमारी की तथा दो लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी छापेमारी के दौरान बैंस के खिलाफ उसके ऋण मामले को लेकर विजिलेंस में केस दर्ज हो गया। केस दर्ज होने पर बैंस उच्च न्यायालय पहुंच गये और उच्च न्यायालय ने जिस तर्ज में इस मामले में टिप्पणियां की है उनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला बहुत कमजोर है। बैंस को जो ऋण बैंक ने स्वीकृत किया उसमें बैंक ने स्वतः ही कटौती कर दी जबकि बैंस ने इस ऋण के लिए जो संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी थी उसकी कीमत 2018 में 75 करोड़ आंकी गई थी। परन्तु बाद में बैंक प्रबंधन ने बैंस को संद्धर्भ में ले बिना ही उसकी कीमत 20 करोड़ कर दी। यहां यह स्वभाविक प्रश्न उठता है कि मनाली में जिस जमीन की कीमत 2018 में 75 करोड़ थी उसकी कीमत 2023 में 20 करोड़ कैसे रह गयी। अब जब बैंक में ई.डी. ने दखल दिया है और बैंस का रिकॉर्ड तलब किया तब उसकी फाइल ही बैंक ने गायब कर दी। यह फाइल गायब होने पर बैंक ने अपने अधिकारियों के खिलाफ जांच आदेशित कर दी है। बैंस के केस की फाइल ही बैंक द्वारा गायब कर दिये जाने से बैंस द्वारा बैंक प्रबंधन पर लगे जा रहे आरोप स्वतः ही गंभीर हो जाते हैं। फिर ओ.टी.एस. को लेकर भी यह सामने आ चुका है कि बैंक द्वारा लायी गयी यह योजना स्वतः ही लैप्स हो गयी है क्योंकि इसमें छः माह तक कोई कारवाई ही नहीं हुई है और नियमों के मुताबिक योजना में गैप आने पर इसको पुनः लागू करने के लिये आर.बी.आई. और नाबार्ड से नये सिरे से अनुमति लेनी पड़ती है। पंजीयक सहकारी सभाएं ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह अनुमति लेना अनिवार्य है। परन्तु बैंक प्रबंधन ने अपने ही स्तर पर ओ.टी.एस. को पुनः चालू कर दिया और 45 करोड़ का ऋण 21 करोड़ में सेटल कर दिया। बैंक में घटे इस सबके परिदृश्य में बैंस द्वारा लगाये जा रहे सारे आरोप स्वतः ही प्रमाणित हो जाते हैं। क्योंकि बैंस ने यह दावा किया है कि उसने इस संद्धर्भ में उससे मिले हर व्यक्ति की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है। यह रिकॉर्डिंग ई.डी. और सी.बी.आई. को भी उपलब्ध करवा दिये जाने का दावा बैंस ने किया है। बैंस ने यह आरोप लगाया है कि उसकी अपने ऋण मामले में मनाली में बैंक के पास गिरवी रखी गयी जमीन को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को देने की योजना बनायी गयी थी। प्रियंका गांधी को यह जमीन देने की बात बैंस को ज्ञानचन्द के माध्यम से सूचित की गयी थी। बैंस के मुताबिक इस सबकी उसने रिकॉर्डिंग कर रखी है। स्वभाविक है कि जब ई.डी. को कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध करवाया गया होगा तभी ई.डी. ने इस मामले में कदम उठाया होगा। वैसे ही ई.डी. पर यह आरोप है कि वह राजनीतिक आकांओं के इशारे पर काम करती है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति जिस मोड पर आ पहुंची है उसके परिदृश्य में भी यह माना जा रहा है कि हिमाचल में अगले दो-तीन माह में कुछ बड़ा घटेगा। क्योंकि यदि बैंस की जमीन प्रियंका गांधी को दिये जाने का संदेश किसी भी नेता ने दिया है और उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ई.डी., सी.बी.आई. तक पहुंच चुकी है तो उसके राजनीतिक अर्थ बहुत दूरगामी हो जाते हैं यह तय है।

प्रभावी शासन और जनसहभागिता से वन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। देवभूमि हिमाचल ने एक बार पुनः यह साबित किया है कि यह प्रदेश देश के सबसे हरित और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक राज्यों में से एक है। पिछले दो दशकों में प्रदेश के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कुल वन क्षेत्र वर्ष 2003 में 14,353 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023 में 15,580.4 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25.73 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है।

इसी प्रकार प्रदेश का वृक्ष क्षेत्र 2003 में 491 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 855.07 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कुल क्षेत्रफल के 0.88 प्रतिशत से बढ़कर 1.53 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह वृद्धि वर्तमान प्रदेश सरकार के सतत वनीकरण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और जनसहभागिता आधारित वन प्रबंधन के सफल प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश की यह उपलब्धि व्यापक पौधरोपण अभियानों, सरकार की विभिन्न योजनाओं और स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों व वन सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत संस्थाओं की भागीदारी से वनीकरण अभियानों को नई गति मिली है। प्रत्येक संगठन को पांच हेक्टेयर तक के बंजर या क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। एक हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए राशि निर्धारित अनुपात के अंतर्गत जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पौधों की जीवित रहने की दर के सत्यापन के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्थानीय प्रजातियों के पुनर्स्थापन, उन्नत नर्सरी तकनीकों और जलागम आधारित भूमि प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे प्रदेश में वनस्पति घनत्व और जैव विविधता में वृद्धि हुई है।

संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) और नई भागीदारी आधारित वन पुनर्स्थापन योजनाओं के तहत लोगों को वन संसाधनों का स्वामित्व और आजीविका से जुड़ा लाभ मिला है, जिससे पारिस्थितिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।

प्रदेश के ये वन महत्वपूर्ण जलागम क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जो उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों को जल प्रदान करते हैं, कृषि उत्पादकता को बनाए रखते हैं, स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं और प्रकृति से जुड़ी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपराओं को भी सशक्त बनाते हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खु ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की यह उपलब्धि नीति-निष्ठा, वैज्ञानिक वन प्रबंधन और जनसहभागिता का प्रमाण है जिसके माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का जलवायु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र, समग्र भू-प्रबन्धन और जैव विविधता संरक्षण पर बढ़ता ध्यान प्रदेश की भारत की पेरिस समझौते और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत की गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जारी है।